नीतीश ने बिहार के विधानसभा चुनावों की बिसात बिछाई

जद (यू) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश के चतुर दांव ने भाजपा की मुश्किल बढ़ाई

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- नीतीश ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पुनः दोहराई और केन्द्र सरकार से इस बारे में आग्रह किया और अति पिछड़ों को दिए गए आरक्षण को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी रखी।
- नीतीश की ये दोनों मांगें आश्चर्यजनक नहीं हैं पर इससे उन्होंने संकेत दे दिया है कि, बिहार में एन.डी.ए. के एकछत्र नेता वही हैं।
- मोदी सरकार के लिए नीतीश की ये दोनों मांगें, खासकर आरक्षण कोटा संबंधी मांग को मानना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा करने से अन्य राज्य भी यही मांग करने लगेंगे।
- नीतीश, मोदी सरकार की दुविधा को जानते हैं, इसलिए वे विधानसभा चुनाव करवाने की मांग पर भी जो दे रहे हैं, ताकि, आरक्षण की बात करके उन्होंने जो वोट बैंक तैयार किया है उसे कहीं राजद न हथिया ले।

नई दिल्ली, 29 जून। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग पुनः दोहराई तथा बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण के कोटा में की गई बढ़ोतरी को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर जोर दिया है। ऐसी मांग करके उन्होंने अगले वर्ष राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के अपनी पार्टी की रणनीतिक योजना पेश कर दी है और इसके साथ ही भाजपा के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है। आज दिल्ली में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक में, पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय झा को भी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया।

कुमार द्वारा उठाई गई दोनों मांगों में कोई नई बात नहीं है क्योंकि इन बातों से भी यह संकेत मिलता है कि वे बिहार में एन.डी.ए. गठबंधन में निर्विवाद नेता के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखना चाहते हैं। कुछ दिन पहले से, प्रदेश भाजपा के कुछ नेतागण यह मांग करते आ रहे हैं कि पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। कुमार ने विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग दोहराकर भाजपा के उस खेमे को भी प्रभाव शून्य करने की कोशिश की है जो उनका विरोध करता है यही नहीं इससे भाजपा नेतृत्व भी रक्षात्मक मुद्रा में आ जाएगा।

भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने कुमार सरकार के उस प्रस्तावित संकल्प का समर्थन किया था जिसमें राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मंजूर किया गया था। बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग को लेकर कुमार पिछले कार्यकाल में भी एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास गये थे। इसलिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस मांग को सीधे तौर पर मुश्किल से ही नकार पाएगा।

एन.डी.ए. की नवगठित सरकार के लिए जे.डी.यू. की यह मांग स्वीकार करना भी काफी मुश्किल है जिसमें प्रदेश सरकार ने आरक्षण कोटा को 65 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है और इसे संविधान की नौंवी अनुसूचि में शामिल करने की मांग की है। एक बार यह कार्य हो जाता है तो राज्य सरकार के निर्णय को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मान लो यह कर दिया जाता है तो ऐसी ही मांगें अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी उठाई जाएगी। संभावना है कि आर.जे.डी. नेता तेजस्वी यादव आगामी कुछ महीनों में इस मुद्दे पर जबरदस्त दांव खेलेंगे। कुमार चाहते हैं कि प्रदेश में चुनाव जल्दी हो, क्योंकि उन्हें डर है कि आरक्षण के मुद्दे के समाधान में विलम्ब होने से तेजस्वी व उनकी पार्टी आर.जे.डी. को उनके द्वारा अति पिछड़ा समुदाय (ई.बी.सी.) के लोगों में सुनियोजित मेहनत कर बनाए गए वोट बैंक को तोड़ने में तेजस्वी व उनकी पार्टी को मदद मिलेगी। अतः यह अति महत्वपूर्ण है कि आरक्षण पर कुमार के दावे स्पष्ट और पारदर्शी कार्य योजनाओं द्वारा समर्थित हैं।

दो क्लासमेट्स बनेंगे भारत की दो सेनाओं के प्रमुख

नई दिल्ली, 29 मई। देश के सैन्य इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब 2 क्लासमेट (लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी) भारतीय सेना और नौसेना के प्रमुख बनेंगे। मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल, रीवा से दोनों की पढ़ाई-लिखाई हुई है। उपेंद्र द्विवेदी कक्षा 5वीं-ए से स्कूल में एक साथ थे। यह 1970 के दशक के शुरुआत की बात है। खास बात यह भी है कि दोनों अधिकारियों के रोल नंबर एक-दूसरे के आसपास थे।

मु.मंत्री भजनलाल भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए

- भाजपा कार्यालय में हुई इस बैठक में, लोकसभा चुनावों में कुछ सीटों पर मिली हार के कारणों की समीक्षा तथा उप चुनाव पर चर्चा हुई।

जयपुर, 29 जून (का.सं.)। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में शनिवार देर शाम को कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया।

इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश सहप्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा नेता शामिल हुए।

भाजपा कोर कमेटी की यह बैठक लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक है। इस बैठक में प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चुनावों में हुई हार के कारणों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही बैठक में, प्रदेश की जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा एक अन्य बैठक में, प्रदेश में एक राज्यसभा सीट खाली होने के बारे में चर्चा की गई।

दिल्ली की बारिश जानलेवा बनी, 12 लोगों की मौत

- पहली ही बारिश में दिल्ली का हाल खराब हो गया है तथा मौसम विभाग ने दिल्ली में अभी और बारिश की चेतावनी दी है।
- आई.एम.डी. ने अगले चार दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। गत शुक्रवार को बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में चार-चार फुट पानी भर गया था।

नई दिल्ली, 29 जून। दिल्ली में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जगह-जगह जमा पानी जानलेवा साबित हो रहा है। सिराजपुर अंडरपास के पास शनिवार को दो लड़कों की डूबकर मौत हो गई। वहीं ओखला अंडरपास से गुजरने की कोशिश कर रहे एक शख्स की मौत हो गई। इसके साथ दिल्ली में बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 12 लोगों की भी मौत हो गई है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में बारिश अभी थमने वाली नहीं है। आईएमडी ने अगले चार दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

ओखला अंडरपास में शनिवार को एक शख्स की डूबकर मौत हो गई। बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन ओखला औद्योगिक क्षेत्र सूचना मिली की एक शख्स पानी में डूब गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि एक व्यक्ति बेहोश होकर पानी में डूबा हुआ है। मृतक स्कूटर चला रहा था। व्यक्ति को एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, सिरसपुर अंडरपास के पास एक 12 साल के लड़के के डूबने की सूचना 02.25 बजे पुलिस थाना बादली को मिली। इसके बाद मौके पर एक टीम को रवाना कर दिया गया। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि मेट्रो के पास अंडरपास में करीब 2.5-3 फुट तक पानी भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड ने तलाशी अभियान चलाया और 2 बच्चों के शव बरामद किए। इनमें से एक की पहचान जीएसडी निवासी सिरसपुर के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला नहाने के दौरान डूबने का लग रहा है। पुलिस 174 सीआरपीसी की के तहत कार्रवाई कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश से जुड़े हादसों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है।

जयराम रमेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"आंध्र प्रदेश के बारे में अभी तक संकल्प पारित क्यों नहीं किया गया है जबकि नए प्रधानमंत्री ने 30 अप्रेल को धार्मिक शहर तिरुपति में पुरजोर तरीके से इसका वादा किया था।"

जे.डी. (यू) व टी.डी.पी. ने भाजपा की लोकसभा सीटों की संख्या इस शर्त पर बढ़ाने के लिए समझौता किया था कि प्रधानमंत्री मोदी उनके दोनों प्रदेशों के लिए विशेष राज्य का दर्जा घोषित करेंगे।

जयराम ने निशाना साधा कि, नीतीश कुमार एवं एन. चन्द्रबाबू नायडू उनके राज्य के लिए विशेष दर्जा देने की मांग करने से अब शर्मा रहे हैं।

बंगाल के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहे अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर ना केवल विराम लगाने की कोशिश की बल्कि एक तरह से प्रधानमंत्री के इस वादे की पोल खोल दी कि वे सहयोगात्मक संघवाद के मार्ग पर चल रहे हैं। आरोप था कि एन.डी.ए. सरकार ने विभिन्न राज्यों की गैर-भाजपा सरकारों को राज्यपाल की शक्तियों से सत्ता से बेदखल किया। इसी तरह से, दिल्ली में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार और लैफ्टिनैंट गवर्नर नजीब जंग के बीच वर्ष 2015 और 2016 में एक सत्ता संघर्ष देखने को मिला। केन्द्र ने लैफ्टिनैंट गवर्नर कार्यालय के जरिए केजरीवाल सरकार के प्रशासन में अवरोध डालने जारी रखे। नजीब जंग के बाद केन्द्र सरकार ने अनिल बैजल और फिर वर्ष 2022 में वी.के. सक्सेना को लैफ्टिनैंट गवर्नर बनाया।

युवाओं के हितों पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ ही खेल प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए संभाग स्तर पर खेल सुविधाएं विकसित हो रही हैं ताकि "मिशन ओलंपिक" के लिए युवाओं को प्रतिस्पर्धी माहौल और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध हो सकें।

शर्मा ने कहा कि, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए विभागों में रिक्त पदों एवं सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त पदों का कलेण्डर बनाकर भर्तियां आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष विभिन्न राजकीय सेवाओं के 70 हजार पदों पर भर्तियां की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश में युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रदेश में जैम्स एवं ज्वेलरी पार्क, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा हैंडीक्राफ्ट पार्क स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन, निर्माण, सेवा, एमएसएमई, कृषि, गैर-परंपरागत ऊर्जा में निवेश एवं ढांचागत सुधारों के जरिये प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, स्किल डवलपमेंट के माध्यम से युवाओं में कौशल संवद्धर्न किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि, भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा करने वाले सावधान रहें, क्योंकि प्रदेश में सरकार बदल गई है और युवाओं के हितों पर कुठाराघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने पेपरलीक मामलों की त्वरित जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

राजकीय सेवाओं में नवनियुक्त कार्मिकों से संवाद के दौरान प्रशिक्षु आरएएस अधिकारी आकांक्षा दुबे ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस हो रहा है। सरकार के विभागों में नौकरी पाने वाले कई अन्य ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया और अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

कार्यक्रम में कौशल, नियोजन एवं उद्यिमता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी थे, उन्होंने कहा कि राजकीय सेवाओं में नवनियुक्त कार्मिक मेहनत एवं लगन से समाज और जरूरतमंद की मदद करके सकारात्मक परिवर्तन लाएं।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजकीय सेवा में आकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। उन्हें उम्मीद की है कि नवनियुक्त कार्मिक अच्छा कार्य करेंगे।

संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक फैसला लिया गया और मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को राजकीय सेवाओं में आने की प्रेरणा मिलेगी।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि, राजकीय सेवा में काम करते हुए नवनियुक्त कार्मिक कड़ी मेहनत एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमन्त गेरा, कौशल, रोजगार एवं उद्यिमता विभाग के शासन सचिव पी.सी. किशन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में नवनियुक्त कार्मिक उपस्थित हुए और सभी जिला मुख्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी एवं नवनियुक्त कार्मिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

लद्दाख: अभ्यास...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में यह नदी है जिसमें अभ्यास से पहले पानी ज्यादा नहीं था। अधिकारीयों का कहना है कि राहत और बचाव का काम तत्काल शुरू कर दिया गया है। बाकी चार जवानों के शवों का भी तलाशी अभियान चलाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा, लद्दाख में नदी पार करते समय टैंक पर सवार सेना के पांच जवानों की मौत होने की घटना से गहरा दुख हुआ है। हम अपने बहादुर जवानों की अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे।

बीते साल लद्दाख में सेना का एक वाहन खाई में गिर गया था। इसमें नौ जवानों की मौत हो गई थी। बताते चलें कि पहाड़ी नदियों में कई बार बादल फटने या फिर भूस्खलन होने की वजह से अचानक जल स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में बड़ा हादसा हो जाता है। जानकारी के मुताबिक मारे गए जवानों में एक जेसीओ शामिल है।

'ई.वी.एम. से वोटिंग होने से दो लाख पेड़ कटने से बचे'

नई दिल्ली, 29 जून। केन्द्र सरकार का कहना है कि ई.वी.एम. ने लोकसभा चुनाव में ना केवल सटीक और निष्पक्ष परिणाम दिए हैं बल्कि इससे पर्यवारण की रक्षा भी हुई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, अगर बैलट पेपर से चुनाव कराए जाते तो कम से कम 2 लाख पेड़ काटने पड़ते। उन्होंने कहा, ईवीएम ने ना केवल विपक्ष के झूठ की पोल खोल दी बल्कि यह वृक्षों के संरक्षण के लिए भी उपयोगी साबित हो रही है। एक कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली की बारिश के बाद पैदा हुए हालातों को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया।

तमिलनाडू में "नीट"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विधानसभा में पारित प्रस्ताव में मांग की गई है कि केन्द्र तमिलनाडू को नीट व्यवस्था से अलग कर दे और तमिलनाडू छात्रों के 12वीं के नम्बर्स के आधार पर मैडिकल कोर्स में प्रवेश की अनुमति दे।

सदन द्वारा पारित प्रस्ताव में केन्द्र सरकार से नैशनल मैडिकल कमीशन एक्ट में संशोधन करने और राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था को रद्द करने की मांग की गई हैं क्योंकि नीट में भारी गड़बड़ियां हो रही है और कई राज्यों में इसका भारी विरोध हो रहा है और वे भी अब तमिलनाडू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि नीट पक्षपाती है और इससे ग्रामीण और गरीब तबके के विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा से वंचित हो गए हैं और इससे राज्यों का विद्यार्थियों को बारहवीं के नम्बर के आधार मैडिकल में प्रवेश देने का राज्यों का अधिकार छिन गया है।

गरीबों और ग्रामीण छात्रों के नीट के कारण मैडिकल शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाने के आग्रह पर भाजपा ने कहा कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा व राज्य के मुख्यमंत्री इ.के. पलानी स्वामी ने नीट पास करने वाले राज्यों के छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी थी। भाजपा विधायक नगेन्द्रन ने वॉक् आउट करते समय कहा कि नीट जरूरी है और नीट के खिलाफ प्रस्ताव अस्वीकार्य है।

लेकिन स्टालिन का तर्क था कि नीट से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों से चिकित्सा सेवा प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा नीट 2017 में अनिवार्य की गई थी और इसके खिलाफ विशाल हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। मुख्यमंत्री के पूर्व विधानसभा में नीट के खिलाफ पारित दो प्रस्तावों की भी याद दिलाई, इसके अलावा कई राज्यों में नीट परीक्षा में गड़बड़ी व घोटाले हुए ग्रेस मार्क्स दिए गए बाद में वापस ले लिए गए। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव भी नीट परीक्षा खत्म करने की मांग कर रहे हैं। "तमिलनाडू की आवाज़ पूरे देश की आवाज़ बन गई है।"

कमला हैरिस जीतीं अमेरिका का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- दूसरा विकल्प, डॉनल्ड ट्रम्प को न्यूयॉर्क के न्यायालय ने 35 घटनाओं में दोषी करार दिया, कोर्ट का मानना है कि, कई मुद्दों पर उन्होंने झूठ बोला।
- अतः दोनों बड़ी पार्टियों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में विश्वास नहीं बन रहा है कि, वे योग्य व सक्षम राष्ट्रपति सिद्ध होंगे, तो आम सहमति यह बनती नज़र आ रही है कि, किसी युवा राजनीतिज्ञ को क्यों न राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार प्रोजैक्ट किया जाये और इस दौड़ में भारतीय मूल की कमला हैरिस का नाम सबसे आगे है। कहा जा सकता है कि, उप राष्ट्रपति कमला हैरिस "प्रैसिडेन्सियल डिबेट" की असली विजेता हैं।

जता दिया कि, वो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं और अमेरिकन फोर्सेस के सुप्रीम कमाण्डर का कर्तव्य निभाने के काबिल नहीं है। उदाहरण के लिए किसी एमरजैंसी में रात में तीन बजे उन्हें कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़े तो शायद वो ना कर पाएं।

बाइडन ने दावा किया कि, उन्होंने 15,000 रोजगार सृजित किए। जबकि, पर्यवेक्षकों का कहना है कि करीब डेढ़ करोड़ रोजगार सृजित हुए है। बाइडन ने कहा कि, वरिष्ठ नागरिकों को दो सौ डॉलर मैडिकल सहयोग मिलता है, जबकि वास्तव में दो हज़ार डॉलर की मैडिकल सहायता मिलती है। उन्होंने आंकड़े पूरी तरह उलट-पलट कर दिए।

सी.एन.एन. द्वारा आयोजित डिबेट के बाद, डैमोक्रैटिक पार्टी, जिसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन है, अब सोच रही है कि, बहुत देर हो जाए उससे पहली ही क्या उसे अभी ही अपना प्रत्याशी बदल लेना चाहिए।

स्वाभाविक ही है कि, इस स्थिति में कई नामों पर चर्चा हो रही है। कुछ डैमोक्रैट्स बाइडन की जगह कमला हैरिस को लाने की बात कर रहे हैं। तथापि, एक सच्ची पार्टी निष्ठावान की तरह कमला हैरिस पहले ही कह चुकी हैं कि, डिबेट में बाइडन का प्रदर्शन अच्छा था। अधिकांश श्रेताओं की शिकायत थी कि बाइडन की बातचीत के स्वर दबे हुए, दुर्बोध और भ्रामक हैं। यूरोप के एक कूटनीतिक ने कहा कि अपनी अंग्रेजी अच्छी होने के बावजूद वे बाइडन का बातों का शायद ही कोई अर्थ निकाल सके।

दूसरी ट्रम्प, दृढ़, पूर्व तैयारी के साथ और अपने विषयों में पूरी पकड़ रखते प्रतीत हुए। पूर्व परिचर्चाओं के विपरीत वे ना तो चिल्लाए, ना ही उन्होंने कोई ताना मारा या अपने विषय से भटके ताकि बाइडन को यह कहने का कोई मौका ना मिले कि "आप चुप रहिए।"

एक पर्यवेक्षक, जो कि रिपब्लिकन नहीं था, ने ध्यान दिलाया कि ट्रम्प ने मार्केटिंग की अपनी विशिष्ट प्रतिभा दर्शायी। ट्रम्प से जब 6 जनवरी की घटनाओं से लेकर प्रश्न पूछे गए जिसमें उनके भड़काने पर यू.एस. कैपिटोल, सीनेटर और कानून निर्माताओं पर हमले किए थे, तो उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को अमेरिका दुनिया के शीर्ष पर था, हमेशा की तुलना में अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर थी, टैक्स कम थे, कीमतें स्थिर थी और अमेरिका की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही थी। ट्रम्प की स्थिति कमजोर थी। उन्हें न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में हाल ही 35 इल्ज़ामों में महा-अपराध का दोषी माना गया, तथापि वे कई मुद्दों पर झूठ बोले और यहां तक कि उन्होंने इससे भी इन्कार किया कि उन्होंने कभी किसी पॉर्न स्टार के साथ यौन सम्बंध बनाए थे। इस सैक्स स्कैण्डल पर कोर्ट पहले ही सुनवाई कर चुके हैं जो उनके खिलाफ गई है। इस बात के प्रमाण हैं कि शिकायतकर्ता पॉर्न स्टार को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसा दिया गया था।

ट्रम्प मुस्तैद भी थे और उन्होंने गर्भपात के अमेरिकी महिलाओं के अधिकार के एक ज्वलंत मुद्दे पर सूक्ष्मभेद वाला रुख अख्तियार किया। चूंकि ट्रम्प गर्भपात के अधिकार का विरोध करते रहे थे, इसलिए उन्होंने इस बार यह जानते हुए कि पुराना कड़ा रुख उन्हें वोट नहीं दिला पाएगा, अपने रुख में संशोधन किया है।

यह परिचर्चा, पूरी दुनिया और कूटनीतिकों के बीच आकर्षण का केन्द्र रही क्योंकि अमेरिका के चुनाव परिणाम वैश्विक संबंधों पर एक अर्थपूर्ण प्रभाव डालेंगे। यूरोप के कूटनीतिक इस डिबेट को गौर से सुनते रहे और अब उन्होंने बाइडन के प्रदर्शन को लेकर सार्वजनिक रुप से निराशा प्रकट कर दी है।

इस परिचर्चा को यदि राष्ट्रपति चुनाव का एक पूर्व सूचक माना जाए तो बाइडन के खिलाफ एक तगड़ी बिसात बिछ चुकी है। पता चला है कि रुस के टीकाकार इस परिचर्चा को लेकर खुश हैं और उन्होंने राष्ट्रपति बाइडन को अपना संयम बरकरार रखने के लिए एक व्यंग्यपूर्ण बधाई दी है। दूसरी तरफ लगता है कि ट्रम्प ने रशियन्स के साथ मित्रता कर ली है।

ट्रम्प ने सार्वजनिक रुप से दावा किया कि अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक इतने फण्ड्स दिए हैं जितने यूरोप के पूरे देशों ने मिलाकर भी नहीं दिए होंगे। यह एक झूठ है और यूक्रेन के लोग इस डिबेट को लेकर निराश हैं। यदि ट्रम्प चुनाव जीतते हैं तो यूक्रेन निश्चित रुप से अमेरिका का सम्पूर्ण समर्थन खो देगा और रुस सफल हो जाएगा।

ट्रम्प ने अपने पुराने अंदाज में "नाटो" को नीचा दिखाना जारी रखा। उन्होंने धमकी दी कि यदि वे फिर से सत्ता में आए तो अमेरिका की नाटो से सम्बद्धता समाप्त कर देंगे। यूरोप इस विचार के साथ जीवित रहने के बारे में सोच रहा है, खासतौर पर उस स्थिति में, जबकि उसका सामना शत्रुतापूर्ण रुस से है, जो पश्चिमी यूरोप को प्रत्यक्ष चुनौती दे रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अब किसी मूल्य आधारित व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनका कहना है किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसने स्वयं के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित में काम किया हो।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908